



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 17, 1971/आषाढ़ 26, 1893

No. 12]

NEW DEHI, SATURDAY, JULY 17, 1971/ASADHA 26, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 17th July 1971

No. 3/17/71-AIS(IV).—In the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 3/12/66-AIS(IV), dated the 25th January, 1967, the President had been pleased to appoint officers named therein, recruited under sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, to the Orissa Cadre of the Indian Forest Service with effect from the 1st October, 1966. It is now notified for general information that as a result of the decisions of the Supreme Court of India in Writ Petitions Nos. 173 to 175 of 1967 and in Special Leave Petitions No. 766/70 and 1574 to 1578 of 1970 in the Supreme Court of India, the appointments of the officers named in the aforesaid notification to the Indian Forest Service have been rendered *ab initio* void. Consequently, the Central Government proposes to take further steps to make fresh recruitment under sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966.

मंत्रिमंडल सचिवालय

कार्मिक विभाग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1971

सं० 3/17/71-अ० भा० से० (4).—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० 3/12/66-ए० आई० एस (4), दिनांक 25-1-1967 में, भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 4 के उप-नियम (1) के अधीन किये गये अधिकारियों को जिन के नाम उनमें दिये गये हैं राष्ट्रपति ने भारतीय वन सेवा के उड़ीसा संवर्ग में पहली अक्षतूषर, 1966 से नियुक्त किया था अब सामान्य सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि 1967 को रिट याचिकाओं सं० 173 से 175 तक में और भारत के उच्चतम न्यायालय में 1970 की विशेष अवकाश याचिकाओं संख्या 766/70 और 1574 से 1578 तक में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के फलस्वरूप उपर्युक्त अधिसूचना में आये अधिकारियों के नामों की नियुक्तियां प्रारंभ से ही अमान्य घोषित की गई हैं। इसके फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार का विचार भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम 1966 के नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन नयी भर्ती करने के लिए, आगे कारवाई करने का है।

No. 3/19/71-AIS(IV).—In the following notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, namely:—

1. No. 3/16/66-AIS(IV), dated 9th February, 1967.
2. No. 3/37/67-AIS(IV), dated 28th May, 1968.
3. No. 3/53/67-AIS(IV), dated 17th July, 1968.

the President had been pleased to appoint officers named therein, recruited under sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, to the West Bengal Cadre of the Indian Forest Service with effect from the 1st October, 1966. It is now notified for general information that as a result of the decisions of the Supreme Court of India in Writ Petitions Nos. 173 to 175 of 1967 and in Special Leave Petitions No. 766/70 and 1574 to 1578 of 1970 in the Supreme Court of India, the appointments of the officers named in the aforesaid notifications to the Indian Forest Service have been rendered *ab initio* void. Consequently, the Central Government proposes to take further steps to make fresh recruitment under sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966.

ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

सं० 3/19/71-अ० भा० से० (4).—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में, अर्थात् :—

1. सं० 3/16/66-ए० आई० एस (4), दिनांक 9-2-1967
2. सं० 3/37/67-ए० आई० एस (4), दिनांक 28-5-1968

3. सं० 3/53/67-ए०आई०एस (4), दिनांक 17-7-1968.

भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 4 के उप-नियम (1) के अधीन किये गये अधिका-
कारियों को जिन के नाम उन में दिये गये हैं राष्ट्रपति ने भारतीय वन सेवा के पश्चिमी बंगाल
संवर्ग में पहली अक्टूबर, 1966 से नियुक्त किया था अब सामान्य सूचना के लिए यह अधिसूचित
किया जाता है कि 1967 की रिट याचिकाओं सं० 173 से 175 तक में और भारत के उच्चतम
न्यायालय में 1970 की विशेष अर्काष याचिकाओं सं० 766/70 और 1574 से 1578 तक में
भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के फलस्वरूप उपर्युक्त अधिसूचनाओं में आये अधिकारियों के
नाम की नियुक्तियां प्रारंभ से ही असम्यक् घोषित की गई हैं। इसके फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार का
विचार भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 4 के उप-नियम (1) के अधीन नयी भर्ती
करने के लिए, आगे कारवाई करने का है।

असा आर० जार्ज,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार।

